

Directorate of Institutional Finance
Chhattisgarh

No. 983 /DIF/2015

dated - 17/11/2015

To,

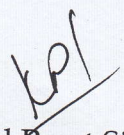
✓ Dy. General Manager & Convener
State Level Bankers' Committee,
Chhattisgarh,
Raipur - 492 001

Subject: Restructure of loans in rain deficit areas.

A D.O. letter no. 38-11/2015-DM dated 19 October, 2015, had been received from Joint Secretary, Govt. of India, Ministry of Agriculture, Department of Agriculture & Cooperation. Attention has been drawn to RBI circular dated 21.08.2015, whereby State Level Bankers Committees/District Level Consultative Committees/Banks to take a view on rescheduling of loans if the crop loss is 33% or more. The banks may allow a maximum repayment period up to 2 years (including the moratorium period of 1 year) if the loss is between 33% and 50%. If the crop loss is 50% or more, the restructured period for repayment may be extended to a maximum period of 5 years (including the moratorium period of one year).

In this regard it can be mentioned that drought has been declared in 110 tehsils of the State. Therefore, SLBC may be requested to act as per the instructions given by Ministry of Agriculture in this regard.

Enclosed: As above



(Kamal Preet Singh)
Director

Endt no. 984 /DIF/2015

dated - 17/11/2015

Copy to -

1. Secretary, Government of Chhattisgarh, Department of Finance, Mantralaya, Naya Raipur (C.G.) for information.
2. Deputy Secretary, to Chief Secretary, Government of Chhattisgarh, Mantralaya, Naya Raipur (C.G.) for information.

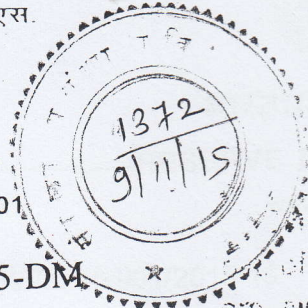

(Kamal Preet Singh)
Director

Directorate of Institutional Finance

01st Block, 4th Floor, Indrawati Bhawan, Naya Raipur, (C.G.)

Ph.No.0771- 2510840, Fax No. 0771 -2510841, e-mail; dif.cg@gov.in

राजेश कुमार सिंह, आई.ए.एस.
संयुक्त सचिव
भारत सरकार
कृषि मंत्रालय
कृषि एवं सहकारिता विभाग
कृषि भवन, नई दिल्ली-110001



Rajesh Kumar Singh, IAS

Joint Secretary

Government of India

Ministry of Agriculture

Department of Agriculture & Cooperation

Krishi Bhawan, New Delhi-110001

19th October, 2015

DO No.38-11/2015-DM

SECRETARY
Govt. of Chhattisgarh
Form No. Dak-654/CS/2015
Date 29 OCT 2015

As you are aware, rainfall deficit during Kharif 2015 has resulted in damage to the crops in many States like Maharashtra, Karnataka, Telangana, Andhra Pradesh, Uttar Pradesh & Bihar. There have been reports from the States besides those in print and electronic media.

2. One of the important reliefs, that the farmers need to be provided with relates repayments of loans. As per the guidelines of Reserve Bank of India dated 01.07.2015, the Banks are empowered to restructure loans in rain deficit areas. The RBI has further reviewed the order and decided vide letter dated 21.08.2015 (copy enclosed) to allow State Level Bankers' Committees/District Level Consultative Committees/Banks to take a view on rescheduling of loans if the crop loss is 33% or more. The Banks may allow a maximum repayment period upto 2 years (including the moratorium period of 1 year) if the loss is between 33% and 50%. If the crop loss is 50% or more, the restructured period for repayment may be extended to a maximum period of 5 years (including the moratorium period of one year).

3. Accordingly, it is requested that necessary instructions may be issued to the concerned for implementation of these guidelines and provide timely relief to the farmers.

Yours sincerely,

(Rajesh Kumar Singh)

for min sec. please to
28 OCT 2015
AGS, Agr. / S(Rew) / S(Pin)

Shri Vivek Kumar Dhand
Chief Secretary
Govt. of Chhattisgarh

DIF

ADIF
KA



भारतीय रिज़र्व बैंक

RESERVE BANK OF INDIA

www.rbi.org.in

RBI/2015-16/156

FIDD No. FSD.BC.12/05.10.001/2015-16

August 21, 2015

The Chairman/Managing Director/Chief Executive Officer
All Scheduled Commercial Banks
(excluding Regional Rural Banks)

Madam/Dear Sir

**GUIDELINES FOR RELIEF MEASURES BY BANKS
IN AREAS AFFECTED BY NATURAL CALAMITIES**

Please refer to our Master Circular FIDD.No.FSD.BC.01/05.10.001/2015-16 dated July 1, 2015 containing 'Guidelines for Relief Measures by Banks in Areas affected by Natural Calamities'. Considering that Government of India has, vide their notification dated April 8, 2015, reduced the criteria of crop loss from 50 percent to 33 percent for providing input subsidy (compensation) to the farmers, the above guidelines have been reviewed.

2. It has been decided to allow State Level Bankers' Committees/District Level Consultative Committees/banks to take a view on rescheduling of loans if the crop loss is 33% or more. Banks may allow a maximum period of repayment of up to 2 years (including the moratorium period of 1 year) if the loss is between 33% and 50%. If the crop loss is 50% or more, the restructured period for repayment may be extended to a maximum of 5 years (including the moratorium period of one year). The relevant paras (5.5, 5.6, 6.3 and 6.7) of the guidelines have been suitably amended and the updated Master Circular has been placed on our website (www.rbi.org.in) simultaneously.

3. Please acknowledge receipt.

Yours faithfully

(Madhavi Sharma)
Chief General Manager

वित्तीय समावेशन और विकास विभाग, केन्द्रीय कार्यालय, 10वीं मंजिल, केन्द्रीय कार्यालय भवन, शहीद भगत सिंह मार्ग, पोस्ट बॉक्स सं. 10014, मुंबई - 400001
Financial Inclusion & Development Dept., Central Office, 10th Floor, Central Office Building, Shahid Bhagat Singh Marg, P.B.No.10014, Mumbai-1

टेली Tel:022-22601000 फैक्स:91-22-22621011/22610943/22610948 ई-मेल: cgmincfidd@rbi.org.in

हिंदी आसान है, इसका प्रयोग बढ़ाए।

"चेतावनी: रिज़र्व बैंक द्वारा मेल डाक, एसएमएस या फोन कॉल के जरिए किसी की भी व्यक्तिगत जानकारी जैसे बैंक के खाते का नंबर, पासवर्ड आदि नहीं मांगी जाती है। यह धन रखने या देने का प्रस्ताव भी नहीं करता है। ऐसे प्रस्तावों का किसी भी तरीके से जवाब मत दीजिए।"

Caution: RBI never sends mails, SMSs or makes calls asking for personal information like bank account details, passwords, etc. It never keeps or offers funds to anyone. Please do not respond in any manner to such offers.

छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय
महानदी, भवन, नया रायपुर
-:: आदेश ::-

नया रायपुर, दिनांक 16/09/2015

क्रमांक एफ-1-108/राजस्व/राहत/2015, राज्य शासन एतद् द्वारा खरीफ फसल की नजरी आनावारी 2015 के आधार पर निम्नलिखित 22 जिलों की 93 तहसीलों को सूखाग्रस्त घोषित करता है तथा छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 144 के अन्तर्गत आगामी आदेश पर्यन्त समस्त राजस्व वसूली स्थगित करता है ।

क्र.	जिला	सूखाग्रस्त तहसीलों का नाम
1.	रायपुर	(1) रायपुर (2) आरंग (3) अमनपुर (4) तिल्दा
2.	गरियाबंद	(1) गरियाबंद (2) राजिम (3) मैनपुर (4) छुरा (5) देवमोग
3.	धमतरी	(1) कुरुद (2) मगरलोड (3) नगरी
4.	महासमुंद	(1) महासमुंद (2) पिथौरा (3) बागबहरा (4) सराईपाली (5) बसना
5.	दुर्ग	(1) पाटन
6.	बालोद	(1) बालोद (2) डौंडीबोहरा (3) डौंडी (4) गुरुर (5) गुण्डरदेही
7.	बेमेतरा	(1) साजा (2) थानखम्हरिया (3) नवागढ़
8.	राजनांदगाँव	(1) छुईखदान (2) खैरागढ़ (3) डोंगरगढ़ (4) राजनांदगाँव (5) अम्बागढ़ चौकी (6) मोहला (7) मानपुर (8) डोंगरगाँव (9) छुरिया
9.	बिलासपुर	(1) बिलासपुर (2) बिल्हा (3) मस्तुरी (4) पेण्डारोड (5) पेण्ड्रा (6) मरवाही
10.	मुंगेली	(1) मुंगेली (2) पथरिया (3) लोरमी
11.	कोरबा	(1) कोरबा (2) करतला (3) कटघोरा (4) पोड़ीउपरोड़ा (5) पाली
12.	रायगढ़	(1) रायगढ़ (2) पुसौर (3) सारंगढ़ (4) बरमकेला (5) घरघोड़ा (6) तमनार (7) धरमजयगढ़ (8) खरसिया (9) लैलुंगा
13.	जशपुर	(1) मनोरा (2) दुलदुला (3) कांसाबेल (4) फरसाबहार
14.	बलरामपुर	(1) बलरामपुर (2) सामरी (3) शंकरगढ़ (4) रामानुजगंज (5) राजपुर (6) वाङ्गफनगर
15.	सूरजपुर	(1) प्रतापपुर
16.	कोरिया	(1) बैकुण्ठपुर (2) सोनहत (3) मनेन्द्रगढ़ (4) खड़गवा (5) भरतपुर
17.	बस्तर	(1) तोकापाल (2) दरमा (3) बस्तर (4) लोहंडीगुड़ा
18.	कोण्डागांव	(1) फरसगांव (2) माकड़ी (3) केशकाल (4) बड़ेराजपुर

निरंतर.....2

//2//

19.	नारायणपुर	(1) नारायणपुर
20.	दन्तेवाड़ा	1) दन्तेवाड़ा (2) गीदम (3) कटेकल्याण (4) कुआंकोण्डा (5) बचेली
21.	सुकमा	(1) कोन्टा
22.	बीजापुर	1) बीजापुर (2) भैरमगढ़ (3) भोपालपटनम् (4) उसूर
93 तहसील		

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(के०आर० पिस्टा) 16/9/2015

सहस्र आयुक्त/सचिव

छत्तीसगढ़ शासन,

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

नया रायपुर, दिनांक 16/09/2015

पृ. क्रमांक एफ 1-108/राजस्व/राहत/2015,
प्रतिलिपि :

1. माननीय राज्यपाल के प्रमुख सचिव, राजभवन, छत्तीसगढ़, रायपुर ।
2. माननीय मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर ।
3. समस्त मान.मंत्रीगण/संसदीय सचिव, छ०शासन, रायपुर ।
4. मुख्य सचिव के उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर ।
5. अध्यक्ष, राजस्व मण्डल छत्तीसगढ़, बिलासपुर ।
6. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय रायपुर ।
7. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा रायपुर ।
8. संभागीय आयुक्त, रायपुर/दुर्ग/बिलासपुर/सरगुजा/बस्तर छत्तीसगढ़
9. कलेक्टर जिला/रायपुर/महासमुन्द/गरियाबंद/धमतरी/दुर्ग/राजनांदगाँव/बालोद/बेमेतरा/बिलासपुर/मुंगेली/कोरबा/रायगढ़/जशपुर/बलरामपुर/सुरजपुर/कोरिया/बस्तर/कोण्डागाँव/नारायणपुर/बीजापुर/सुकमा(छत्तीसगढ़)
10. आयुक्त, जनसंपर्क, रायपुर ।

सहस्र आयुक्त/सचिव 16/9/2015

छत्तीसगढ़ शासन,

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

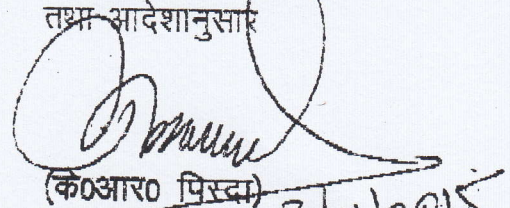
छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय
महानदी, भवन, नया रायपुर
-- आदेश --

नया रायपुर, दिनांक 3/11/2015

क्रमांक एफ-1-108/राजस्व/राहत/2015, राज्य शासन एतद् द्वारा पुनः खरीफ फसल की नजरी आनावारी 2015 के आधार पर निम्नलिखित 7 जिलों की 17 तहसीलों को सूखाग्रस्त घोषित करता है तथा छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 144 के अन्तर्गत आगामी आदेश पर्यन्त समस्त राजस्व यसूली स्थगित करता है ।

क्र.	जिला	सूखाग्रस्त तहसीलों का नाम
1.	बेमेतरा	(1) बेरला (2) बेमेतरा
2.	कबीरधाम	(1) कवर्धा (2) बोडला (3) सहसपुर-लोहारा (4) पण्डरिया
3.	जॉजगीर-चौपा	(1) बलौदा
4.	बस्तर	(1) जगदलपुर (2) बकावण्ड
5.	कोण्डागोव	(1) कोण्डागोव
6.	कोंकर	(1) कोंकर (2) नरहरपुर (3) भानुप्रतापुर (4) दुर्गकोन्दल (5) अन्तागढ़ (6) चारबामा
7.	नारायणपुर	(1) ओरछा
		17 तहसील

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(के०आर० मिस्दा)

सहस्र आयुक्त / सचिव

छत्तीसगढ़ शासन,

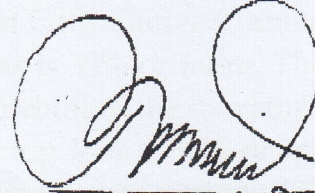
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

निरन्तर-----2/

/ / 2 / /

पृ. क्रमांक एफ 1-108/राजस्व/राहत/2015, नया रायपुर, दिनांक 3/11/2015
प्रतिलिपि :

1. माननीय राज्यपाल के प्रमुख सचिव, राजभवन, छत्तीसगढ़, रायपुर ।
2. माननीय मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर ।
3. समस्त मान.मंत्रीगण/संसदीय सचिव, छ0ग0शासन, रायपुर ।
4. मुख्य सचिव के उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर ।
5. अध्यक्ष, राजस्व मण्डल छत्तीसगढ़, बिलासपुर ।
6. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव छत्तीसगढ़ शासन,मंत्रालय रायपुर ।
7. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा रायपुर ।
8. संभागीय आयुक्त, दुर्ग/बिलासपुर/बस्तर छत्तीसगढ़
9. कलेक्टर जिला बेमेतरा/कबीरखाम/जॉजगीर-चौपा/ बस्तर/ कोण्डागांव/ नारायणपुर/कोंकर (छत्तीसगढ़)
10. आयुक्त, जनसंपर्क, रायपुर ।



राहत आयुक्त/सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

3/11/2015